टाइम्स ऑफ़ पीडिया

TIMES OF PEDIA

ٹائمس آف پیڈیا

अनोखे अंदाज़ और निराले तेवर के साथ इंसाफ़ की डगर पर

NEW DELHI Page 12 Price Rs. 3.00

www.timesofpedia.com

WEEKLY HINDI, ENGLISH, URDU

WED 04 MARCH - TUE 10 MARCH 2026 | VOL. 14. ISSUE 10 | RNI No. DELMUL/2012/47011

मध्य पूर्व में बदलती स्थिति के बीच भारत पूरी तरह तैयार - ऊर्जा आपूर्ति मज़बूत

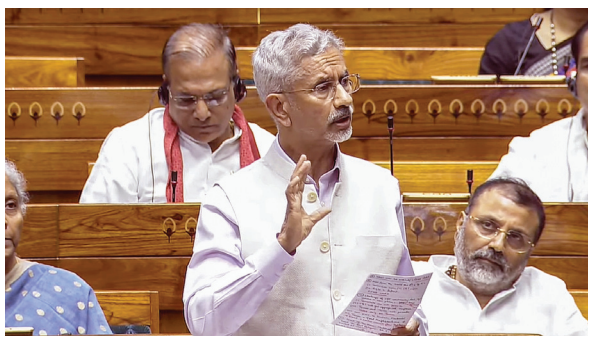

नई दिल्ली: मध्य पूर्व में उथल-पुथल की स्थिति और वैश्विक ऊर्जा स्थिति में हो रहे बदलावों को ध्यान में रखते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने मौजूदा परिस्थितियों में देश की तैयारियों के बारे में मीडिया को अवगत कराया।

जानकारी के अनुसार-भारत वैश्विक स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों का तीसरा सबसे बड़ा आयातक, चौथा सबसे बड़ा शोधक और पांचवां सबसे बड़ा निर्यातक है। देश में कच्चे तेल और पेट्रोल, डीजल और एटीएफ सहित प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार है, जिससे मध्य पूर्व से उत्पन्न होने वाली अल्पकालिक समस्याओं का निदान किया जा सके। यह भी बताया गया कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाकर अपनी आबादी के लिए ऊर्जा की उपलब्धता और सामर्थ्य सुनिश्चित की है। भारतीय ऊर्जा कंपनियों के पास अब ऐसे ऊर्जा स्रोतों तक पहुंच है जो होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर नहीं गुजरते। ऐसे कार्गो उपलब्ध रहेंगे और होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने के दौरान आपूर्ति में अस्थायी रूप से होने वाली रुकावटों को दूर करने में मदद करेंगे। देश भर में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति और स्टॉक की स्थिति पर लगातार नज़र रखने के लिए मंत्रालय ने ख्ब्मस्त्र नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। वर्तमान में, सरकार के पास पर्याप्त स्टॉक है। भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। लगातार निगरानी के आधार पर, सरकार को उम्मीद है कि यदि आवश्यक हुआ तो स्थिति को और सुधारने के लिए चरणबद्ध तरीके अपनाए जा सकते हैं।

सरकार ने अपने पक्ष में कहा कि भारत ने ऊर्जा आपूर्ति के स्रोतों को विविध बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसके अलावा रणनीतिक भंडारण, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने पर भी जोर दिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि बदलते वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दीर्घकालिक योजना के साथ आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही देश की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए सभी संभावित विकल्पों पर ध्यान दिया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक ऊर्जा बाजार में उतार-चढ़ाव और भू-राजनीतिक तनाव के बीच भारत को संतुलित और दूरदर्शी नीति अपनानी होगी। उनका कहना है कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के साथ-साथ नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी तेजी से निवेश बढ़ाना समय की आवश्यकता है।

डीटीसी बस दुर्घटना में दो लोगों की मौत, इलाक़े में अफरा-तफरी

नई दिल्ली: (टॉप ब्यूरो) राजधानी के निहाल विहार क्षेत्र में सोमवार सुबह हुई एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मृत्यु हो गई। तेज रफ्तार दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की बस की चपेट में आने से रविकांत शर्मा और कमलजीत शर्मा की जान चली गई। इस घटना के बाद इलाके में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

जानकारी के अनुसार रविकांत शर्मा परिवहन से जुड़ा काम करते थे और सोमवार सुबह स्कूटी से अपने कार्यस्थल के लिए निकले थे। उनके बड़े भाई शशिकांत भी उसी मार्ग से अपनी फैक्ट्री जा रहे थे। रास्ते में दुर्घटनास्थल पर रविकांत की स्कूटी पड़ी देखकर उन्हें शंका हुई। आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर दुर्घटना की जानकारी मिली। शशिकांत ने अपने छोटे भाई की पहचान उसके जूतों से की। गंभीर रूप से घायल रविकांत को स्थानीय लोगों की मदद से ई-रिक्शा द्वारा सत्यभामा अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें महाराजा अग्रसेन अस्पताल भेजा गया। वहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रविकांत अपने पीछे पत्नी और पांच वर्ष की एक बेटी को छोड़ गए हैं।

केजरीवाल प्रकरण की सुनवाई कर रहीं न्यायाधीश पर 'आप' ने उठाए प्रश्न

नई दिल्ली: (टॉप ब्यूरो) कथित मद्य नीति घोटाले से जुड़े प्रकरण की सुनवाई कर रहीं उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा को लेकर आम आदमी दल ने गंभीर प्रश्न उठाए हैं। दल ने पूछा है कि न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा का भारतीय जनता दल से क्या संबंध है। यह प्रश्न दल के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने एक संवाददाता सम्मेलन में उठाया।

उल्लेखनीय है कि कथित मद्य नीति घोटाले के मामले में विचारण न्यायालय ने ख्त्र फरवरी को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित सभी ख्फ आरोपितों को आरोपमुक्त कर दिया था। इसके बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। इस याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ कर रही है। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान न्यायालय ने प्रारंभिक स्तर पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को कुछ राहत प्रदान की। इसके बाद भारतीय जनता दल के कुछ नेताओं के बयान सामने आए, जिनमें कहा गया कि इस मामले में अभी बहुत कुछ शेष है। इन्हीं बयानों के आधार पर आम आदमी दल ने न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर प्रश्न उठाए हैं।

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब प्रकरण अभी न्यायालय में विचाराधीन है, तब किसी राजनीतिक दल के नेताओं का यह कहना कि आगे क्या होने वाला है ।

पश्चिम एशिया पर भारत और दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रियों के बीच वार्ता

विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने आज दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ पश्चिम एशिया की स्थिति, जिसमें ऊर्जा संबंधी मुद्दे भी शामिल थे, पर विचार-विमर्श किया। दोनों नेताओं ने भारत और दक्षिण कोरिया के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा की। डॉ. जयशंकर ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी साझा की।

Editor/Owner/Printer/Publisher: Ali Aadil Khan, K-2-A-001, Abul Fazal Enclave-l, Jamia Nagar, Okhla, ND - 25. ***Printed at:*** Shobi Offset Press, 2818, Gali Gadhiaiya, Kuchachalan, Daryaganj, ND. -2

ईरान - अमेरिका तनाव का भारत पर भयानक असर

Ali Aadil Khan
Editor

ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव केवल पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं है — इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, सुरक्षा और विदेश नीति पर पड़ सकता है।

भारत अपनी लगभग 85-90 % कच्चे तेल की ज़रूरत आयात से पूरी करता है। अगर ईरान-अमेरिका टकराव बढ़ा जो कड़ी के देशों पर भी असर डालेगा और होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) बाधित हुआ, तो कच्चे तेल की कीमतों में तेज़ उछाल तय है।

होर्मुज़ जलडमरूमध्य एक बहुत संकरा समुद्री रास्ता है, जो फारस की खाड़ी (Persian Gulf) को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। यह ईरान और ओमान (मुसंदम प्रायद्वीप) के बीच स्थित है।

विशेषज्ञों के मुताबिक तेल में हर $10 की बढ़ोतरी से भारत का GDP ग्रोथ रेट 0.3% घट सकता है . महंगाई दर 0.3-0.4% बढ़ सकती है . करंट अकाउंट डेफिसिट पर दबाव बढ़ेगा, तेल महंगा होगा तो रुपया और कमजोर पड़ेगा. आयात महंगा होगा ईंधन, ट्रांसपोर्ट और रोज़मर्रा की चीज़ों की कीमतें बढ़ सकती हैं. और इसका सीधा असर भारत की आम जनता की जेब पर पड़ेगा। जिसको देश की जनता समझ नहीं रही है, इलाक़े में जंग के नकारात्मक असर से अभी जनता वाक़िफ़ नहीं है.

व्यापार और भारतीय कंपनियों पर असर

हालांकि एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, ईरान संकट से भारत की वैश्विक ट्रेडिंग पर अभी तक फिलहाल बड़ा झटका नहीं पड़ा है. लेकिन अगर तनाव लंबा चला, तो निर्यात, शिपिंग लागत और निवेशकों का भरोसा और कारोबार दोनों प्रभावित हो सकते हैं ।

अमेरिका की सख्ती और भारत की कूटनीतिक दुविधा

अमेरिका ने ईरान के तेल नेटवर्क और 'शैडो फ्लीट' पर नए प्रतिबंध लगाए हैं. इन प्रतिबंधों में भारत से जुड़ी कंपनियों और व्यापार मार्गों का नाम भी आया है, जिससे भारत पर राजनयिक दबाव और बढ़ सकता है. ऊर्जा के क्षेत्र में खरीद और व्यापार नीति जटिल हो सकती है.

सामरिक और रणनीतिक असर

ईरान क्षेत्र में अस्थिरता का सीधा मतलब है मध्य-पूर्व में बसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, चाबहार पोर्ट जैसी रणनीतिक परियोजनाओं पर अनिश्चितता और भारत की क्षेत्रीय कूटनीति पर दबाव.

चाबहार पोर्ट (ईरान) भारत के लिए एक रणनीतिक, आर्थिक और भू-राजनीतिक परियोजना थी. लेकिन ईरान पर प्रतिबंध और क्षेत्रीय तनाव के कारण भारत को कई स्तरों पर नुकसान उठाना पड़ा है।

चाबहार का मकसद था पाकिस्तान को बायपास कर अफगानिस्तान, मध्य एशिया और रूस तक व्यापार मार्ग खोलना लेकिन प्रोजेक्ट की धीमी रफ्तार से भारत की रणनीतिक पकड़ कमजोर हुई चीन के ग्वादर पोर्ट (पाकिस्तान) को बढ़त मिली.

दुसरे ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते निवेश में अनिश्चितता बढ़ी फाइनेंसिंग और बैंकिंग चैनल जटिल हो गए भारत को कई बार परियोजना की गति कम करनी पड़ी इन सब कारणों से भारत की कूटनीतिक स्वतंत्रता सीमित हुई।

तीसरे अगर चाबहार पूरी क्षमता से चलता, तो भारत को मध्य एशिया में बड़ा व्यापारिक लाभ मिलता एक्सपोर्ट, लॉजिस्टिक्स और एनर्जी ट्रेड बढ़ता लेकिन देरी के कारण संभावित अरबों डॉलर का व्यापारिक अवसर हाथ से निकल गया।

इसके अलावा चाबहार भारत के लिए अफगानिस्तान में मानवीय और आर्थिक संपर्क का प्रमुख ज़रिया था. तालिबान के सत्ता में आने और अस्थिरता के बाद भारत का क्षेत्रीय प्रभाव कमजोर हुआ लॉजिस्टिक और डिप्लोमैटिक पहुंच सीमित हुई। जबकि चाबहार योजना में देरी और अनिश्चितता से चीन ने पाकिस्तान-ईरान क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत की भारत की क्षेत्रीय रणनीतिक बढ़त कमजोर पड़ी है . कुल मिलाकर ईरान और खाड़ी के किसी भी देश में अस्थिरता का सीधा नकारात्मक प्रभाव भारत पर पड़ता है.

और अमेरिका , योरोप और चीन हमेशा इसी हिकमत के साथ अपनी सियासी गोटियां चलते हैं जबकि भारत योरोप और अमेरिका पर आँखें बंद करके भरोसा करता है .

चाबहार केवल एक बंदरगाह नहीं था बल्कि यह भारत की रणनीतिक दूरदृष्टि की परीक्षा थी। इस परियोजना में देरी, प्रतिबंध और कूटनीतिक दबाव के बीच सवाल यही है क्या भारत इस प्रोजेक्ट को फिर से अपनी ताक़त बना पाएगा, या यह एक अधूरा सपना बनकर रह जाएगा ?

निष्कर्ष

ईरान-अमेरिका तनाव केवल एक विदेशी संकट नहीं बल्कि यह भारत की अर्थव्यवस्था, तेल सुरक्षा और आम जनता की ज़िंदगी से जुड़ा मसला है। अगर यह संघर्ष बढ़ता है, तो भारत को तेल महंगाई, आर्थिक दबाव और कूटनीतिक और सांप्रदायिक संतुलन सभी मोर्चों पर सतर्क रहना होगा। 'राजनीति की इस शतरंज में दांव भले ही बड़े हों, लेकिन हर चाल का असर आम इंसान की ज़िंदगी पर पड़ता है और हमारी लीडरशिप की यही सबसे बड़ी चिंता है, जो दुर्भाग्यवश दिखाई नहीं देती.

ईरान के आईआरजीसी ने अमरीकी और इस्राइली ठिकानों पर 17वां हमला किया

प्रेस टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के इस्लामी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर –आईआरजीसी ने आज अमरीकी और इस्राइली ठिकानों पर 17 वां हमला किया। आईआरजीसी की जमीनी सेना ने ईरान पर इस्राइली-अमरीकी हमलों का तीन बड़े अभियानों से जवाब दिया।

आज ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस – 4 के एक और चरण की घोषणा करते हुए आईआरजीसी के जनसंपर्क विभाग ने बताया कि इस्राइली-अमरीकी संयुक्त हमलों के तुरंत बाद उसकी जमीनी सेना ने कब्जे वाले क्षेत्रों और अमरीकी ठिकानों पर 230 से अधिक ड्रोन दागे।

आईआरजीसी ने कहा कि एरबिल और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर दर्जनों ड्रोन दागे गए हैं और उत्तरी इराक में कई आतंकवादी गुटों के मुख्यालयों को नष्ट किया गया है। ये बच्चों की हत्या करने वाले हमलावरों के खिलाफ आईआरजीसी के बहादुर सैनिकों की पहली कार्रवाई थी।

आईआरजीसी ने दावा किया कि ईरान के जवाबी हमलों ने बहरीन में एक प्रमुख अमरीकी हवाई अड्डे को पंगु बना दिया है और कमान केंद्र नष्ट हो गए हैं। आईआरजीसी के अनुसार, युद्ध के पहले दो दिनों में ईरान के जवाबी हमलों में विभिन्न अमरीकी ठिकानों पर तैनात 680 से अधिक अमरीकी सैनिक हताहत हुए हैं। ईरानी अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया है कि क्षेत्र में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना आत्मरक्षा के समान है।

अमरीका ने व्यापक सैन्य अभियान के पहले दस दिनों में ईरान में 5000 से अधिक ठिकानों पर हमले किए

अमरीका ने व्यापक सैन्य अभियान के पहले दस दिनों में ईरान में 5000 से अधिक ठिकानों पर हमले किए हैं। जबकि लगभग 50 ईरानी नौसैनिक जहाजों को नुकसान पहुँचाया गया है या नष्ट कर दिया गया है। अमरीकी केंद्रीय कमान द्वारा जारी विवरण के अनुसार, 28 फरवरी को शुरू हुए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के लिए वायु सेना, नौसेना और मिसाइल प्रणालियों का इस्तेमाल किया गया। अमरीकी केंद्रीय कमान ने कहा कि अभियान के तहत जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया, उनमें सैन्य कमान और नियंत्रण केंद्र, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर मुख्यालय भवन, खुफिया ठिकाने और एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियाँ शामिल हैं।

क़तर एयरवेज़ की उड़ानों से दोहा में फंसे लगभग एक हज़ार भारतीय पिछले तीन दिनों में भारत लौटे

कतर में भारतीय दूतावास ने बताया है कि दोहा में अल्पकालिक यात्रा पर फंसे लगभग एक हजार भारतीय, पिछले तीन दिनों में कतर एयरवेज की उड़ानों से भारत लौट चुके हैं। दूतावास के अनुसार कतर एयरवेज आज दिल्ली, मुंबई और कोच्चि के लिए तीन उड़ानें संचालित करेगी। साथ ही बताया कि सऊदी वीजा का अनुरोध करने वाले यात्रियों के मामलों को भी देखा जा रहा है।

NOTICE:
Times of Pedia does not guarantee, directly or indirectly, the quality or efficacy of any product or services described in the advertisements or other material which is commercial in nature in this Newspaper. Furthermore, Times of Pedia assumes no responsibility for the consequences attributable to inaccuracies or errors in the printing of any published material from the news agencies or articles contributed by readers. It is not necessary to agree with the views published in this Newspaper. All disputes to be settled in Delhi Courts only.

ईरान ने तेल आपूर्ति रोकी तो अमेरिका करेगा कड़ी सैन्य कार्रवाई: ट्रम्प

वॉशिंगटन : (टॉप ब्यूरो) अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने चेतावनी दी है कि यदि तेहरान होर्मुज़ जलडमरूमध्य के रास्ते तेल आपूर्ति को रोकने की कोशिश करता है तो अमेरिका ईरान के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई को और तेज कर सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यह संघर्ष उम्मीद से पहले समाप्त हो सकता है।

समाचार सम्मेलन को संबोधित करते हुए ट्रम्प ने कहा कि अमरीकी बल पहले ही ईरान की वायुसेना और नौसेना को गंभीर नुकसान पहुँचा चुके हैं। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि युद्ध उनके द्वारा पहले बताए गए चार सप्ताह के समय से भी पहले समाप्त हो सकता है। इस बीच, ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने तुरंत

प्रतिक्रिया देते हुए चेतावनी दी कि यदि अमेरिका और इज़राइल के हमले जारी रहते हैं तो वे क्षेत्र से 'एक लीटर तेल' भी बाहर नहीं जाने देंगे।

गार्ड्स के एक प्रवक्ता ने कहा कि युद्ध कब समाप्त होगा, इसका फैसला वाशिंगटन नहीं बल्कि ईरान करेगा। हाल के दिनों में पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका और ईरान के बीच बयानबाजी भी तेज हो गई है। विश्लेषकों का मानना है कि यदि यह टकराव और बढ़ता है, तो क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा बाजार दोनों पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ सकता है।

अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने दोनों देशों से संयम बरतने और कूटनीतिक समाधान तलाशने की अपील की है, ताकि क्षेत्र में तनाव और बढ़ने से रोका जा सके।

इधर विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि यदि होर्मुज़ जलडमरूमध्य में किसी प्रकार की सैन्य झड़प होती है या तेल आपूर्ति बाधित होती है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज़ उछाल आ सकता है। इसका असर भारत समेत कई तेल आयात करने वाले देशों पर पड़ सकता है। तेल महंगा होने से महंगाई बढ़ने, परिवहन लागत में वृद्धि और वैश्विक व्यापार पर दबाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है।

कूटनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव वैश्विक राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था को और जटिल बना सकता है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों की भूमिका भी अहम मानी जा रही है, ताकि बातचीत और कूटनीति के माध्यम से क्षेत्र में स्थिरता कायम रखी जा सके।

Beyond Bravery and Blame: A Call for Wisdom in Times of War

Najmuddin A Farooqi

Public memory is often short but conscience is not. I was among the first to condemn the attack on Iran; my message circulated in my WhatsApp groups at 3:43 PM on February 28 stands as proof. I did so not out of political alignment, but out of principle. Out of 116 articles I have written 46 in Urdu and 70 in English one idea consistently emerges: human life is sacred.

When I say "human," I mean every human being, regardless of status, nationality, sect, or belief whether a king or the most downtrodden soul. In my view, human life is the most precious trust on earth.

I detest nothing except violence whether physical aggression or verbal hostility. I believe in forgiveness and reconciliation. When I am wrong, I do not hesitate to apologise the moment I realise my mistake. Sadly, such reciprocity is rare. Too often, restraint is mistaken for weakness. Yet I maintain what I have always said, I hate nothing except violence.

Having said that, moral clarity requires intellectual honesty. The ongoing conflict is not a tale of heroism; it is, in many respects, a tragic culmination of strategic miscalculations and political arrogance. What some describe as "bravery" may, in reality, be reckless adventurism. No Arab or Muslim country can be fairly held responsible for the hostility that Iran now faces from multiple quarters or for the degree of diplomatic isolation it experiences today.

For years, Iran has projected its military prowess often with deliberate emphasis on deterrence and regional influence. There is no denying its capabilities. Among sections of the Shia community worldwide, faith in Iranian leadership has, at times, assumed an almost sanctified aura. Social media narratives in recent years have amplified carefully curated images of figures such as Ali Khomeini, portraying him in moments of prayer, humility and benevolence, reinforcing a perception of exceptional piety and moral authority. While personal devotion deserves respect, governance demands more than symbolism. Statesmanship requires prudence, foresight and an acute awareness of consequences.

Everything I have written in the past has been grounded in verifiable facts and supported by references. I rarely express opinions without evidence and I remain accountable for my words. My concern today is not to assign blame for its own sake, but to urge sober reflection. The past nine months have been devastating for Iran. Since the reported precision strikes beginning on June 25, which resulted in the deaths of 20 senior officials, the country has witnessed an unprecedented escalation of turmoil. This was followed by extraordinary mass protests on the streets of Tehran and other major cities, during which thousands were reportedly killed in clashes with security forces.

Now, most tragically, 48 top officials including the Supreme Leader have reportedly fallen victim to this widening conflict. Regardless of political affiliations, such losses constitute a profound national trauma. No nation emerges stronger from the decapitation of its leadership.

Yet even amid grief and uncertainty, we must resist the temptation to embrace exaggerated fears. The notion that Israel will evolve into a so-called "Greater Israel," incorporating the Gulf Cooperation Council (GCC) states, allegedly with identical designs supported by the United States, is more speculative rhetoric than strategic reality.

History demonstrates that wars often end not with maximalist ambitions fulfilled, but with recalibrated boundaries and exhausted societies seeking stability.

As Muslims, our primary concern should not be the triumph of one state over another, but the preservation of life, dignity and regional stability. We should sincerely pray that a pragmatic and progressive leadership emerges within Iran, one capable of introspection rather than defiance for its own sake.

The first task of any new leadership must be honest self-assessment: Where did we go wrong ? Was it in the relentless drum-beating of self-declared invincibility ? Or in neglecting the necessity of constructive engagement with the international community?

True strength lies not in rhetoric, but in wisdom. Not in isolation, but in balanced diplomacy. And not in vengeance, but in safeguarding the lives of one's people. History will judge leaders by the lives they protect, not the slogans they proclaim.

Rising Hate: Rays of Hope

Prof. Ram Puniyani

Communal Hate is the most divisive tool. Roughly the degree of violence is proportional to the prevalence and accentuation of 'Hate'. This in turn leads to polarization and the situation where ghettoisation and accompanying phenomenon become the norm. As we have witnessed the rise of this phenomenon at a rapid pace during the last few decades. The religious minorities in particular feel intimidation leading them to a sense of helplessness and marginalisation. The hate has been constructed through issues of cow, love jihad, and demonization of Muslim kings among others.

A recent study by Centre for Study of Society of Society and Secularism, Mumbai presented by Irfan Engineer, Neha Dabhade and Diya Padalkar goes into details and type of hate Speeches. As per this study the number of Hate speeches declined from 2024 to 2025. They point out that though the total number of these speeches may have come down as per the data base they have used, there may be other sources of data, which cannot be accessed easily. The hate speech begins from the top is amply demonstrated by this meticulous report. The report says, "The highest number of hate speeches was made by Nitesh Rane, Minister of Fisheries and Port Development in the Maharashtra Government (10), followed by Yogi Adityanath, Chief Minister of Uttar Pradesh (6), and Himanta Biswa Sarma, Chief Minister of Assam, and Union Home Minister Amit Shah made five. The Prime Minister, Narendra Modi, made three hate speeches."

In the backdrop of this hate speech starting from the top and percolating down, while assuming more aggressive form, there are few incidents, which can indicate that despite such intense atmosphere of hate, there are series of incidents, which have happened in the recent past which indicate that though the dominant element is to abuse the religious minorities, there are many in the society who are sticking to love and amity for all.

Though there is a prevalence of demonizing religious minorities, there are still many individuals who are sticking to the values of love and amity, still upholding the values of harmony in a multi religious society. For them the Ganga Jamuni Tehzeeb and respect of all religious communities still matters as the core values of their life. This incident we had discussed in the last article, but now we have a better understanding of this incident. In Kotdwar in Uttarakhand, Deepak Kumar is the shining example of this. He manages a Gymnasium. When he heard some Bajrang Dal Activists harassing Vakil Ahmad, he came to intervene. Vakil Ahmad a seventy-year-old man who has been running "Baba School Dress" for the last 30 years. The hooligans confronted him saying how dare he, a Muslim, use the word Baba for his shop as this word is for Hindus. Their level of ignorance won't tell them that the baba word is coming from Persian, used both for Hindus and Muslim seers. Deepak Kumar retaliated by saying that it is the owner's choice as to what name he gives to his shop. When the Bajrang Dalis asked his name Deepak Kumar said Mohammad Deepak, in the deeper traditions of Indian syncretism. Now as he became known Rahul Gandhi invited him and congratulated him. Deepak Kumar is planning a Yatra, 'Insaniyat Yatra' to give the message of peace.

The other major incident giving some hope is from Lucknow University. Within its campus is the Lal baradari Mosque where the Muslim residents of campus used to offer Namaz. Since it is very old and not in a good condition, it has been locked and the residents are offering namaz outside the mosque. When some Muslim students during this month of Ramadan went to offer Namaz there, they were prevented by some other right-wing students from doing so. Remarkably again at this time other students from NSUI, AISA guarded them and they could offer their prayers.

In yet another incident which took place in Jalalpur village under Bommalaramaram mandal in Yadadri Bhuvanagiri district on 15 February, unknown persons entered the Jama Masjid and damaged parts of the structure. Worshippers discovered the incident the next morning when they arrived for prayers. Members of the mosque committee saw the damaged part of the mosque, washroom doors which were destroyed and also the microphone system. Beer bottles were found inside the premises. Several copies of the Holy Qur'an were reportedly scattered in the compound. When this came to be known many Hindu traders reached there and undertook to get the mosque repaired at their expense! Another disturbing event was the blanket distribution in Kareda village in Tonk district of Rajasthan: A former BJP member of parliament, Sukhbir Singh Jaunpuria. While distributing the blankets he asked the name of one of the elderly women. As it turned out she was a Muslim. He took the blanket back and said we don't give this to those who abuse Modi. Three other Muslim women also returned their blankets. This insulting act infuriated others. Later workers from other parties not only condemned him but also gave blankets to the Muslim women

One Hindu woman who calls herself Hindu Sherani, Riddhima Sharma, visited the Gogavir Temple (also called Gogamedi) in Rajasthan She saw a priest there whose name was Hussain. She shouted at him as to how dare he come into the temple to do Jihad. Other devotees objected to this telling her that the temple has the tradition of having a Muslim priest! With so many incidents of love and amity, the dominant atmosphere of hate is very heartening. What does it show? It seems that hate spreaders are dominant but get away due to state patronage. The Indian ethos of love and harmony is still very much there though not as visible. In the prevalent atmosphere where hate mongers have state patronage to the extent that the state Central Government recently funded a meeting of Sanatan Rashtra Shankhnaad, in Bharat Mandapam was given 63 Lakhs. In this event speeches against Muslims where the theme was demand for Hindu Rashtra! All this shows the resilience of Indian ethos which still survives despite the campaigns spreading Hate!

JIH Chief Raises Concern Over Women's Safety, Economic Distress and West Asia Conflict

New Delhi: (TOP Bureau) The President of Jamaat-e-Islami Hind (JIH), Syed Sadatullah Husaini, on Monday expressed concern over rising crimes against women, increasing economic hardships and the escalating military conflict in West Asia. He was addressing the monthly press conference at the headquarters of Jamaat-e-Islami Hind in the national capital.

Referring to the upcoming International Women's Day, Husaini said that while the day celebrates women's achievements, the continuing rise in crimes against women highlights the urgent need to ensure their safety, dignity and equal opportunities. Citing data from the National Crime Records Bureau (NCRB), he said more than 4.45 lakh cases of crimes against women were registered in India in 2022. These included rape, sexual assault, domestic violence, trafficking and cruelty by husbands or relatives. The NCRB recorded over 31,000 rape cases during the year, averaging nearly 85 cases a day. Domestic cruelty alone accounted for more than one-third of all reported crimes against women. Husaini also expressed concern over the issue of missing women and girls, noting that every year several lakh women and adolescents are reported missing across the country, many of whom remain untraced. He said women and girls remain vulnerable to trafficking, forced labour, exploitation and sexual violence, and stressed that protecting women's dignity requires strict laws, swift justice and a strong moral and ethical framework in society. Turning to economic issues, the JIH president said the recent Union Budget 2026–27 has raised concerns about growing economic distress. He said the budget focuses heavily on supply-side incentives while giving insufficient attention to income distribution, employment generation and social protection. Husaini warned that global uncertainties and rising crude oil prices due to tensions in West Asia could put additional pressure on the Indian economy. As India imports more than four-fifths of its crude oil, any geopolitical disruption could lead to higher fuel prices, rising inflation and increased financial pressure on households and small businesses.

He also highlighted challenges in the labour market, saying a large portion of the workforce remains engaged in informal and insecure employment. The rapid expansion of the gig economy, he said, has left many young workers without adequate job security, fair wages or social protection. Speaking on the conflict in West Asia, Husaini expressed concern over the ongoing military confrontation involving the United States, Israel and Iran. He warned that continued escalation could destabilise the wider Middle East and called for restraint and diplomatic engagement. He emphasised that lasting peace and stability in the region can only be achieved through dialogue, respect for sovereignty and adherence to international law.

SUBSCRIPTION FORM
TIMES OF PEDIA

Issue	Subscription Price	Years
52	250/-	1
104	500/-	2
260	1,300/-	5
520	2,600/-	10
--	5,000/-	Life

Name :.....
Address :.....
.....
.....
Email:.....
Contact Phone No.....
for donation ☐ /life ☐ /10 yrs ☐ /5 yrs ☐ subscription
The sum of Rupees..... (Rs...../-)
through cheque/DD No.....dt.....

Fill the above form neatly in capital letters and send it to us on the following address :
Times of Pedia, K-2-A-001, Abul Fazal Enclave-I,
Jamia Nagar, Okhla, New Delhi-110025
or email : **timesofpedia@gmail.com**

Also Send us your subscription, membership, donation amount in favour of Times of Pedia, New Delhi
Punjab National Bank,Nanak Pura Branch,
New Delhi-110021
A/C No.1537002100017151, IFS Code : PUNB 0153700

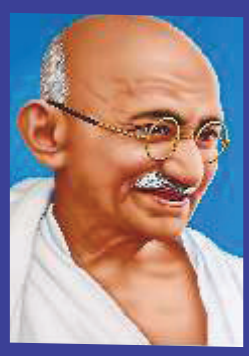

"First, they ignore you, then they laugh at you, then they fight you and then you win."
- Mahatma Gandhi

ADVERTISEMENT TARIFF
TIMES OF PEDIA

Size/Insertion Single	B&W (Rs)	4 Colour (Rs)
Full Page (23.5 x 36.5 cm)	30,000/-	1,00,000/-
A4 (18.7 x 26.5 cm)	20,000/-	60,000/-
Half Page (Tall-11.6 x 36.5 cm)	18,000/-	50,000/-
Half Page (wide-23.5 x 18 cm)	8,000/-	50,000/-
Quarter Page (11.6 x 18 cm)	10,000/-	28,000/-
Visiting Card size (9.5 x 5.8 cm)	3,000/-	10,000/-

MECHANICAL DATA:

Language: English, Hindi and Urdu

Printing: Front and Back - 4 Colours , Inside pages - B&W

No. of Pages: 12 pages (more in future)

Price: Rs. 3/-

Print order: 25,000

Periodicity: Weekly

Material details: Positives/Format of your advertisements should reach us 10 days before printing.

Note: 50% extra for back page, 100% extra for front page

Please Add Rs. 10 for outstation cheques.

50% advance of total add cost would be highly appreciable, in case of one year continue add. Publication cost will reduce 50% of actual cost.

Bank transactions details of TIMES OF PEDIA
Send your subscriptions/memberships/donations etc. (Cheques/DD) in favour of TIMES OF PEDIA New Delhi
Punjab National Bank,Nanak Pura Branch , New Delhi-110021
A/C No.1537002100017151, IFS Code : PUNB 0153700

भारत ने तीसरी बार आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप का ख़िताब जीता

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने विजेता टीम को बधाई दी

नई दिल्ली: (टॉप ब्यूरो) भारत ने इतिहास रचते हुए तीसरी बार आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराया। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम न्यूजीलैंड ने 256 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम 19 ओवरों में मात्र 159 रनों पर ऑल आउट हो गई। जसप्रीत बुमराह ने सर्वोच्च चार विकेट लिए और उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप जीतने पर भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत को यह गौरव प्राप्त है कि वह तीन बार कप जीतने वाला एकमात्र देश है और लगातार दो बार कप जीतने वाली एकमात्र टीम भी है। राष्ट्रपति ने कहा कि इससे क्रिकेट प्रेमियों को अपार खुशी और गर्व का अनुभव हुआ है और यह विभिन्न क्षेत्रों में हमारे युवाओं की प्रतिभा का प्रमाण भी है। उन्होंने आगे कहा कि इस सामूहिक जीत के लिए प्रत्येक खिलाड़ी, संपूर्ण प्रबंधन और सहायक स्टाफ सर्वोच्च प्रशंसा के पात्र हैं।

अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने कहा कि फाइनल में ऐतिहासिक और शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत ने आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के तीन खिताब जीतने वाली पहली टीम बनकर देश के लिए गौरव का क्षण बना दिया है। श्री राधाकृष्णन ने पूरी टीम, सहायक कर्मचारियों और लाखों प्रशंसकों को भी शुभकामनाएं दीं जिनके अटूट समर्थन ने इस उल्लेखनीय उपलब्धि को संभव बनाया। उन्होंने कहा कि पूरा देश इस गौरवशाली जीत का जश्न बड़े गर्व से मना रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टी 20 क्रिकेट विश्व कप जीतकर भारतीय टीम ने यह साबित कर दिया है कि दृढ़ संकल्प, संयम और आत्मविश्वास का मेल ही जीवन में सफलता का मूल मंत्र है। सोशल मीडिया पर एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए मोदी ने कहा कि यह जीत दर्शाती है कि सही दिशा में किए गए परिश्रम से हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने सभी नागरिकों को अपने सपनों को निरंतर और दृढ़ता से पूरा करने की सलाह दी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पूरे टूर्नामेंट में टीम के असाधारण प्रदर्शन और जुझारू क्षमता के प्रदर्शन ने देश के लिए गौरव और गर्व की बात है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व कप में यह विजय दर्शाती है कि दृढ़ संकल्प, संयम और आत्मविश्वास से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने नागरिकों से अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा लेने की अपील की।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी दल के पूरे प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि खिलाड़ियों की जुझारू भावना और शानदार खेल ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है।

भारत की इस ऐतिहासिक विजय के बाद देश के विभिन्न शहरों में खेल प्रेमियों ने उत्साहपूर्वक जश्न मनाया। कई स्थानों पर लोगों ने मिठाइयाँ बांटी, पटाखे जलाए और तिरंगा लहराकर खिलाड़ियों की इस उपलब्धि का स्वागत किया। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि यह जीत आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट को और अधिक मजबूती देगी तथा युवा खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगी।

विशेषज्ञों के अनुसार इस प्रतियोगिता में भारतीय दल की सफलता का प्रमुख कारण खिलाड़ियों की अनुशासनपूर्ण तैयारी, संतुलित टीम चयन और मैदान पर सामूहिक प्रयास रहा। बल्लेबाजों ने जहां आक्रामक और जिम्मेदार खेल दिखाया, वहीं गेंदबाजों ने विरोधी टीम को लगातार दबाव में बनाए रखा। क्षेत्ररक्षण में भी खिलाड़ियों ने फुर्ती और समर्पण का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। खेल जगत के जानकारों का कहना है कि इस जीत से भारतीय क्रिकेट की प्रतिष्ठा और अधिक बढ़ी है। यह उपलब्धि आने वाले वर्षों में नई पीढ़ी के खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी और देश में खेल के प्रति उत्साह को और मजबूत करेगी। पूरे देश के लिए यह जीत गर्व और आनंद का अवसर बन गई है।

इसी क्रम में खेल विश्लेषकों का मानना है कि भारतीय दल की यह सफलता केवल एक प्रतियोगिता की जीत भर नहीं है, बल्कि यह देश में खेल संस्कृति को मजबूत करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। इस विजय ने यह संदेश दिया है कि कठिन परिश्रम, अनुशासन और सामूहिक प्रयास के बल पर किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।विशेषज्ञों का कहना है कि हाल के वर्षों में देश में खेल ढांचे को मजबूत करने, खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने और युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के प्रयासों का सकारात्मक परिणाम अब देखने को मिल रहा है। इसी कारण भारतीय खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं।

क्रिकेट प्रेमियों का भी मानना है कि इस जीत ने देश के युवाओं में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार किया है। कई स्थानों पर युवाओं ने इसे अपने सपनों को साकार करने की प्रेरणा के रूप में देखा है। विद्यालयों और महाविद्यालयों में भी खेल गतिविधियों के प्रति रुचि बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।

ایران پر اسرائیل وامریکہ کا حملہ اور مسلم دنیا

ظفر حسین غزالی

اسرائیل امریکہ کے مشترکہ حملے میں ایران کے سپریم لیڈر اور روحانی پیشوا حجت الاسلام آیت اللہ حسن علی خامنہ ای کی ان کے اہل خانہ کے ساتھ شہادت اور تقریباً165 اسکولی بچیوں کے بہیمانہ قتل نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ حملہ اس وقت ہوا جب امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت کا سلسلہ جاری تھا۔ 2 دن قبل تیسرے دور کی عمان کی ثالثی میں ہوئی گفتگو کے مثبت سمت میں جانے کا دعویٰ تھا۔ حالانکہ اس میں امریکی نمائندے نے نئی شرائط کی فہرست ایرانی نمائندے کو تھمائی تھی۔ جس میں ایران کے تینوں اٹامک مراکز پر تالا لگانا، میزائیل پروگرام بند کرنا اور حماس جیسے گروپوں کی حمایت کو روکنا شامل تھا۔ ایران نے ظاہری طور پر یہ شرائط منظور نہیں کیں لیکن آیت اللہ علی خامنہ ای کے ایک صلاح کار نے کہا تھا کہ اگر جنیوا کی بات چیت صرف اٹامک ہتھیار نہ بنانے تک محدود رہتی ہے تو دونوں ممالک میں سمجھوتا ہوسکتا ہے۔ ویسے بھی ایران ہمیشہ سے اٹامک ہتھیاروں سے انکار کرتا رہا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ اپنے اٹامک پروگرام کو پوری طرح بند نہیں کرسکتا، کیونکہ طوانائی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اسے اس کی ضرورت ہے۔ اگر امریکہ اسرائیل کا حملہ نہ ہوتا تو اگلی میٹنگ ویانا میں ہوتی۔ جس کے بارے میں ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا تھا کہ اب تک کی جتنی بھی بات چیت ہوئی ہے اس میں یہ سب سے سنجیدہ ہوگی۔ ایسا لگتا ہے کہ گفتگو محض ایک بہانہ تھا تاکہ اسرائیل کو تیاری کے لیے زیادہ وقت مل سکے۔ شاید امریکہ اور اسرئیل نے اس حملہ کی تیاری بہت پہلے شروع کی تھی۔ وینزویلا کے صدر کی مجرمانہ گرفتاری اس سلسلہ کی کڑی معلوم ہوتی ہے۔ اس وقت ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ وینزویلا کے تیل پر پہلا حق ہمارا ہے۔ امریکہ جانتا تھا کہ حملہ کی صورت میں ایران آبنائے ہرمز بند کرسکتا ہے۔ ایسی صورت میں وینزویلا سے امریکہ اور یورپ کو تیل کی ترسیل جاری رہے گی۔ جنگ کے دوران ایران نے ہرمز کو بند کرا ایشیائی ممالک کو ہونے والی تیل کی سپلائی بند کردی۔ اس سے جو بھی نقصان ہوگا وہ ایشیائی ممالک کا ہی ہوگا۔ ایران پر امریکہ اسرائیل کے مشترکہ حملہ کے پیچھے کئی تھیوریاں بتائی جا رہی ہیں۔ ایک طبقہ مانتا ہے کہ جب بھی امریکہ یا اسرائیل میں انتخابات قریب آتے ہیں تو وہاں کے حکمراں کامیابی کے لیے جنگ کا سہارا لیتے ہیں۔ ٹرمپ اور نیتن یاہو کو چند ماہ بعد الیکشن میں جانا ہے۔ پالیسیوں اور اقتصادی صورتحال کی وجہ سے امریکی عوام ٹرمپ سے ناراض ہیں۔ امریکہ میں اس حملہ کے حوالے سے جو پول کرایا گیا اس میں صرف 33 فیصد لوگ ہی اس کے حق میں تھے۔ ڈیموکریٹک ہاؤس مائنرٹی لیڈر حکیم جیفریس نے کہا کہ ''ڈونالڈ ٹرمپ ایران پر حملہ کرنے سے پہلے کانگریس سے منظوری لینے میں ناکام رہے تھے''۔ وہیں نیتن یاہو بدعنوانی اور وار کرائم کے سنگین جرائم کا مجرم ہے۔ اقتدار ہاتھ سے جاتے ہی انہیں جیل جانا پڑے گا۔ وہ اپنے ملک سے بھی باہر نہیں جا سکتے، بین الاقوامی عدالت نے ان کے خلاف وارنٹ ایشو کر رکھا ہے۔ وہ کہیں بھی جائیں گے تو گرفتار ہو جائیں گے۔ اپنی جان بچانے کے لیے ایکشن میں کامیابی حاصل کرنا ضروری ہے۔ دوسری تھیوری یہ ہے کہ امریکہ پوری دنیا کے معدنیات اور تیل پر اپنا قبضہ چاہتا ہے۔ وہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے ممالک پر اس کا تسلط اسی مقصد کے لیے ہے۔ مسلم ممالک کے سربراہان کی حفاظت کے نام پر بنے امریکی فوجی اڈوں کا مقصد ان کی نگرانی ہے۔ جبکہ مسلم حکمراں اسے اپنے لیے باعث افتخار تصور کرتے ہیں۔ کئی حضرات اس حملے کو بھی ایران کے وسائل پر قبضہ کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ کئی مبصرین اس پورے معاملہ کو اپسٹین فائلس کے پس منظر میں دیکھ رہے ہیں۔ ان فائلوں میں دنیا کے طاقتور لوگوں کے ناموں کا انکشاف کیا گیا ہے جس کے باعث استعفوں سے لے کر گرفتاریوں تک مختلف کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ کہا گیا ہے کہ ابھی 80 فیصد فائلیں اور ظاہر کی جائیں گی۔ اس طرف سے دنیا کا دھیان ہٹانے کے لیے یہ جنگ چھیڑی گئی ہے۔ مذہبی طبقہ اسے عقیدے کی جنگ مان رہا ہے۔ ڈاکٹر تسلیم رحمانی کا کہنا ہے کہ صیہونیت کا ماننا ہے کہ ظہور دجال کا زمانہ قریب آ گیا ہے اور ان کے استقبال کے اقدامات ضروری ہیں۔ جس کے لیے گریٹر اسرائیل کا قیام لازمی ہے۔ اسرائیل قدیم یہودی بستیوں کو اپنی حکومت کا حصہ بنانا چاہتا ہے۔ اس کا مجوزہ نقشہ اسرائیلی وزیر اعظم اقوام متحدہ میں دکھا بھی چکے ہیں۔ تقریباً پورا مشرق وسطیٰ اس نقشہ میں شامل ہے جس میں موجود ممالک کے ساتھ اسرائیل اپنے سیاسی وسفارتی تعلقات پہلے ہی استوار کر چکا ہے۔ ابراہیمی معاہدہ اس کا شاہد ہے۔ ان ممالک کا فوجی اور اقتصادی انحصار بھی زیادہ تر اسرائیل پر ہے۔ اس راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ایران ہے جو 1979 میں ایرانی اسلامی انقلاب کے بعد سے ہی واضح لفظوں میں اسرائیل کی اس پالیسی کا شدید مخالف رہا ہے، اس لیے کہ اعتقادی طور پر ایرانی حکومت کا بھی یہ ماننا ہے کہ امام مہدی کا ظہور عنقریب ممکن ہے اور ان کے استقبال کی تیاری کی جانی چاہیے۔ اس غرض سے ایرانی انقلاب کے قائدین نے یوم اول سے ہی فلسطینی کاز کی کھل کر حمایت بھی کی اور ہر قسم کی مدد بھی کرتے رہے۔ نیز غزہ اور اسرائیل کی جنگ میں ایران کی یہ مدد واضح طور پر ساری دنیا نے محسوس بھی کی ہے۔ لبنان کا حزب اللہ بھی اسرائیلی سرحد پر واقع ہے۔ ایرانی انقلاب کے بعد وہ بھی اسرائیل کی توسیع پسند پالیسی کی قوت کے ساتھ مخالفت کرتا رہا ہے۔ اسرائیل یہ جانتا ہے کہ چاروں طرف موجود مسلم ممالک سے وہ تنہا مقابلہ نہیں کرسکتا، اس لیے اسے امریکی مدد کی شدید ضرورت رہی ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ مسلم ممالک امریکہ واسرائیل کی منشاء کو نہیں سمجھتے یا غلط صحیح طریقہ سے اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لیے ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ایران پر حملہ کرمٹانے کے لیے امریکہ میں موجود صیہونی لابی کے ساتھ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے بھی ٹرمپ پر دباؤ بنایا تھا۔ ایران نے جون 2025 میں اسرائیل سے 12 دن چلی جنگ کے دوران بین الاقوامی قانون یاد دلایا تھا کہ کوئی بھی ملک اپنی سر زمین کسی ملک کو دوسرے ملک پر حملہ کرنے کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گا۔ اگر کسی ملک کی زمین اس کے خلاف حملہ کے لیے استعمال ہوگی تو ایران اس پر حملہ کرے گا۔ اسی کے تحت ایران نے یو اے ای، سعودی عرب، قطر، بحرین، اردن، ترکیے، کویت سمیت امریکہ کے 28 فوجی اڈوں پر حملہ کیا۔ امریکہ نے اپنے ٹھکانوں سے فوجیوں کو محفوظ جگہ جانے کو کہا۔ اسرائیل ایرانی حملوں کی آڑ میں مشرق وسطیٰ کے ممالک میں بڑے پیمانے پر بم دھماکے کرنے کی سازش کر رہا تھا، جس کا انکشاف قطر اور سعودی عرب میں موساد کے پکڑے گئے ایجنٹ سے ہوا۔ سعودی عرب کی سب سے بڑی تیل ریفائنری آرامکو پر بھی اسرائیل نے ہی حملہ کیا تھا جس کا الزام وہ ایران پر لگانا چاہتا تھا۔ لیکن ایران نے پہلے ہی اس کی وضاحت کر دی تھی کہ اس کا ٹارگیٹ امریکی فوجی ٹھکانے ہیں۔ وہ یہ پیغام دینے میں بھی کامیاب رہا ہے کہ جو امریکہ اپنے بیس کو نہیں بچا سکتا وہ ان کی حفاظت کیسے کرے گا۔ اس کے باوجود مسلم ممالک کی تنظیم او آئی سی نے ایران پر امریکہ واسرائیل کے حملہ کی مذمت کرنے کے بجائے الٹے ایران کی ہی مخالفت کی ہے۔ اچانک امریکہ واسرائیل کے ایران پر حملے میں سپریم لیڈر اور تقریباً 165 چھوٹی بچیوں کی موت نے پوری دنیا کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس کی وجہ سے برطانیہ اور جاپان جیسے ممالک نے بھی امریکہ سے کنارہ کرلیا ہے۔ مسلم ناٹو کی بات کرنے والے ممالک پاکستان، ترکیے اور سعودی عرب کو اس وقت ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کی وفاداری امریکہ کے ساتھ دکھائی دے رہی ہے۔ حالات سے لگ رہا ہے کہ یہ جنگ لمبی چلے گی، اگر ایسا ہوا تو اس کا سب سے زیادہ نقصان ایشیاء اور مسلم ممالک کو بھگتنا پڑے گا۔

حرمین شریفین میں تراویح کے ایمان افروز مناظر

ثناء اللہ صادق تیمی

مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا تقدس دنیا کے تمام مسلمانوں کی نظر میں مسلم ہے۔ مکہ مکرمہ میں ان کا قبلہ ہے اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی ہے اور وہیں اللہ کے آخری نبی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں۔ مسجد حرام مکہ مکرمہ میں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نماز کے برابر اور مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب ایک ہزار نماز کے برابر ہے۔ پوری دنیا سے مسلمان مکہ مکرمہ حج ادا کرنے آتے ہیں جو اسلام کا پانچواں رکن ہے اور اس مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے جو یہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ مسلمان محبت کی پوری شدت اور عقیدت کی گہرائی کے ساتھ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی زیارت کرتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، یہیں غار حراء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بار وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے اور وہیں آپ نے ایک شاندار اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، اسلامی تہذیب کے اصول متعین کیے، ایک انتہائی درجے میں مثالی معاشرہ قائم کیا اور وہیں فوت بھی ہوئے۔

پوری دنیا کے مسلمانوں کی ان دونوں شہروں سے گہری عقیدت وابستہ ہے۔ وہ یہاں آنے کا خواب دیکھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اور یہاں پہنچنے کو اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہیں۔ شعراء شاعری کرتے ہیں، ادباء تحریریں رقم کرتے ہیں اور خوش بیان لوگ اپنی خوش بیانی کے جادو جگاتے ہیں۔

دکھا دے یا الٰہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے
جہاں پر رات دن مولی تیری رحمت برستی ہے

سچی بات بھی یہی ہے کہ جب نگاہیں خانہ کعبہ کا دیدار کرتی ہیں اور مسلمان مسجد نبوی کو دیکھتا ہے تو وہ ایک الگ ہی احساس تلے ہوتا ہے، جیسے بس وہ ہے، حرمین شریفین کی پاکیزگی اور روحانیت ہے اور دنیا جیسے کہیں ہے ہی نہیں۔

کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر
کیا چیز ہے دنیا بھول گیا

حکومت سعودی عرب حرمین شریفین پر خصوصی توجہ صرف کرتی ہے۔ یہاں کے حکمراں اپنے لیے خادم حرمین شریفین کا لقب اختیار کرتے ہیں اور ان کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ حرمین اور ان کے زائرین کو ہر ممکن سہولتیں فراہم کی جائیں اور انہیں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس معاملے میں بطور خاص مملکت سعودی عرب کی کوششیں قابل تعریف ہیں۔ انہوں نے حرمین کی زبردست توسیع کی ہے، پورے نظام کو بہت اچھے انداز میں منظم کیا ہے اور حج وعمرے کے فریضے کو امن وامان کے ساتھ آسانی وسہولت سے بھر دیا ہے۔ دنیا بھر سے مسلمان آتے ہیں اور عمرہ وحج کے فرائض ادا کر کے خوش وخرم واپس جاتے ہیں۔

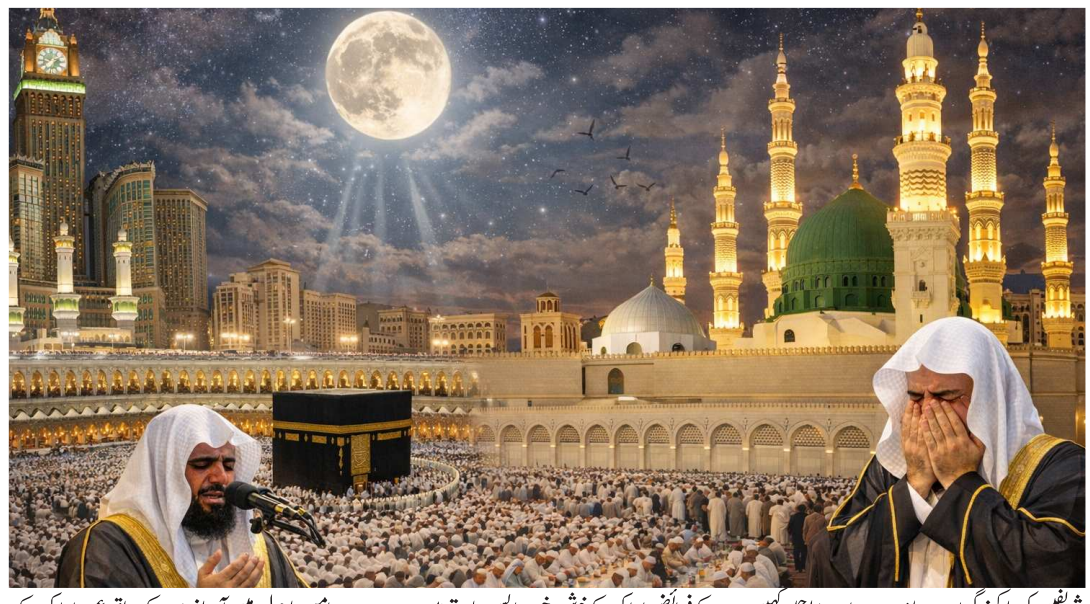

مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں روحانیت کی صبا چلتی ہے، یہاں آنکھوں سے توبہ کے آنسو بہتے ہیں، دلوں میں حق پر چلنے کا ایک عزم بیدار ہوتا ہے، ماضی کے گناہوں کو آہ وگریہ زاری کے تسلسل اور شدت سے دھونے کی کوشش کی جاتی ہے اور پورے سال یہاں روحانیت وپرہیزگاری کی ایک خاص چادر سی تنی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔

رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں یہ کیفیت مزید گہرا جاتی ہے۔ مسلمان روزہ رکھتے ہیں اور اس مہینے میں عمرہ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس مہینے میں عمرہ کرنے کی خاص فضلیت ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے جیسا ہے۔ مسلمان تمام اطراف عالم سے بھاری تعداد میں عمرہ کے لیے آتے ہیں اور پرامن ماحول میں آسانیوں کے ساتھ عمرہ ادا کر کے حکومت سعودی عرب کی کامیاب انتظامی کوششوں کی تعریف کرتے ہیں۔

ماہ رمضان میں فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل وہدایت کی پیروی کرتے ہوئے تراویح کی نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ حرمین شریفین میں تراویح کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ رمضان سے قبل ہی ائمہ کا لائحہ تیار ہو جاتا ہے۔ بھیڑ کی تنظیم کے لیے خصوصی تیاری کی جاتی ہے، سیکورٹی کے اہلکار بڑھا دیے جاتے ہیں، آمد ورفت کے لیے بسوں کا خصوصی انتظام کیا جاتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ حرمین کے زائرین کا مل خشوع وخضوع کے ساتھ تراویح کی سنت ادا کرسکیں۔

واضح رہے کہ دنیا کا سب سے بڑا دسترخوان بھی حرمین شریفین میں ہی لگتا ہے۔ افطار کا ایسا انتظام کہیں اور دیکھنے کو نہیں مل سکتا۔ 10 سے 15 منٹ کے اندر ہزاروں کی تعداد میں تعینات عملہ دسترخوان بچھاتے ہیں، سامان افطار بانٹتے ہیں، روزے دار افطار سے فارغ ہوتے ہیں اور منٹوں کے اندر دسترخوان اٹھا لیا جاتا ہے اور مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ ایک عجیب وغریب روحانی ماحول ہوتا ہے جو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔

حرمین شریفین میں ان ائمہ کو امامت کے لیے منتخب کیا جاتا ہے جو قواعد وضوابط کی رعایت کرتے ہوئے خوش الحانی کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں۔ حرمین اور ان کے احاطوں میں جب قرآن کریم کی آیتیں ان کی شیریں آواز میں سماعتوں سے ٹکراتی ہیں تو دل کی دنیا میں کیا کیا کیفیت گزر جاتی ہے۔

مسجد حرام میں اس مرتبہ رمضان سنہ 1447 ہجری میں شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس، شیخ ڈاکٹر یاسر الدوسری، شیخ ڈاکٹر ماہر المعقلی، شیخ ڈاکٹر عبداللہ الجہنی، شیخ ڈاکٹر ولید شمسان، شیخ ڈاکٹر بدر التر کی اور شیخ ڈاکٹر بندر بلیلہ تراویح کی نماز پڑھا رہے ہیں، جب کہ مسجد نبوی میں شیخ ڈاکٹر عبداللہ البعیجان، شیخ ڈاکٹر عبدالمحسن القاسم، شیخ ڈاکٹر خالد المھنا، شیخ ڈاکٹر عبداللہ القرافی، شیخ ڈاکٹر محمد برہی، شیخ ڈاکٹر صلاح البدیر اور شیخ ڈاکٹر احمد حذیفی تراویح کی نماز میں امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اس طرح حرمین شریفین میں قرآن کریم کی تلاوتوں کی ایمانی خوشبو پھیل رہی ہے۔ ائمہ کرام کی شیریں آواز، اللہ کے کلام کی ہیبت اور مقام کے تقدس سے ایک خاص فضا بنتی ہے اور جب ائمہ ترغیب وترہیب کی آیتوں سے گزرتے ہوئے بے ساختہ رونے لگتے ہیں تو ایک سماں بندھ جاتا ہے۔ حرمین شریفین کے تراویح کے یہ حسین مناظر ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ کا باعث ہوتے ہیں۔

उत्तम नगर होली हत्याकांड: आरोपियों के घरों पर बुलडोज़र कार्रवाई पर उच्च न्यायालय की रोक

नई दिल्ली: दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन हुई 26 वर्षीय युवक की हत्या के मामले में आरोपियों के घरों पर चल रही बुलडोजर कार्रवाई पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने फिलहाल रोक लगा दी है। न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली नगर निगम को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक आरोपियों के घरों को गिराने से संबंधित कोई भी कार्रवाई न की जाए।

न्यायमूर्ति अमित वंशल की एकल पीठ ने आदेश देते हुए कहा कि मंगलवार शाम चार बजे से लेकर बुधवार सुबह दस बजकर तीस मिनट तक किसी भी प्रकार की विध्वंस कार्रवाई नहीं की जाएगी। न्यायालय ने यह आदेश उन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया, जो आरोपियों की माताओं ने अपने घरों को गिराए जाने की आशंका को लेकर दायर की थीं।

उल्लेखनीय है कि चार मार्च को होली के दिन उत्तम नगर क्षेत्र में 26 वर्षीय तरुण भुटोलिया की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कई लोगों को आरोपी बनाया गया है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का वातावरण बन गया और मामला सांप्रदायिक रंग लेने लगा, क्योंकि मृतक हिंदू समुदाय से था जबकि आरोपी मुस्लिम समुदाय से बताए जा रहे हैं। मामले में आरोपियों की माताओं शाहनाज और जरीना ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अपने घरों को गिराए जाने से संरक्षण की मांग की है। शाहनाज आरोपी सोहेल और अयान की मां हैं, जबकि जरीना सह-आरोपी इमरान उर्फ बंटी की मां बताई जा रही हैं।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि हत्या के मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के तुरंत बाद ही नगर निगम ने एक आरोपी से जुड़े मकान के कथित अवैध हिस्से को गिरा दिया। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह कार्रवाई मनमाने और चुनिंदा तरीके से की गई है। उनका कहना है कि जिस मकान को गिराया गया वह न तो सरकारी भूमि पर बना था और न ही किसी सड़क पर अतिक्रमण किया गया था।

याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि नगर निगम कई वर्षों से उस संपत्ति से कर तथा बिजली का बिल वसूलता रहा है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वह संपत्ति मान्यता प्राप्त थी। उन्होंने अपने पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय के वर्ष 2024 के उस निर्णय का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि किसी भी संरचना को गिराने से पहले संबंधित पक्ष को सूचना देना और सुनवाई का अवसर प्रदान करना आवश्यक है।

फिलहाल उच्च न्यायालय ने नगर निगम की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाते हुए मामले की अगली सुनवाई बुधवार को निर्धारित की है, जहां इस विषय पर विस्तार से विचार किया जाएगा।

ईडी याचिका पर केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित सभी को नोटिस जारी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज प्रवर्तन निदेशालय की दायर याचिका पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए। न्यायालय ने अगली सुनवाई की तारीख 19 मार्च तय करते हुए कहा कि इस मामले में उचित अंतरिम आदेश पारित किया जाएगा।

प्रवर्तन निदेशालय ने आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य सभी आरोपियों को बरी करते समय निचली अदालत द्वारा निदेशालय के खिलाफ की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।

प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने बताया कि निचली अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो-सीबीआई द्वारा दर्ज एक मामले के फैसले में निदेशालय के खिलाफ टिप्पणियां की थीं। उन्होंने कहा कि जब ये टिप्पणियां की गईं, तब धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत धन शोधन का मामला विशेष न्यायालय के समक्ष विचाराधीन नहीं था।

पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित किया जाएगा: मुख्य निर्वाचन आयुक्त

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि निर्वाचन आयोग मतदाताओं को डराने-धमकाने की घटनाएं बर्दाश्त नहीं करेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि आयोग सुनिश्चित करेगा कि पश्चिम बंगाल में सभी मतदाता आगामी विधानसभा चुनावों में हिंसा और धमकी से मुक्त वातावरण में भाग लें। चुनाव तैयारियों पर दो दिवसीय समीक्षा बैठक के बाद आज कोलकाता में एक संवाददाता सम्मेलन में कुमार ने कहा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों को बिना किसी डर या पक्षपात के कानून का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने मतदाताओं से शांतिपूर्ण और सहभागी चुनाव सुनिश्चित करने में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण पूरा होने वाला है। उन्होंने बल देकर कहा कि त्रुटिरहित मतदाता सूचियां लोकतंत्र की आधारशिला हैं।

दो दिवसीय समीक्षा बैठक के बाद कोलकाता में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग की प्राथमिकता यह है कि प्रत्येक मतदाता बिना किसी भय, दबाव या हिंसा के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। उन्होंने कहा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे बिना किसी डर या पक्षपात के कानून का कड़ाई से पालन कराएं और चुनाव प्रक्रिया के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखें।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि चुनाव की तैयारियों की लगातार समीक्षा की जा रही है और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण अंतिम चरण में है और इसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा।

उन्होंने जोर देकर कहा कि त्रुटिरहित और पारदर्शी मतदाता सूचियां लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला होती हैं। इसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक पात्र नागरिक को मतदान का अधिकार मिले और चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष बनी रहे।

ज्ञानेश कुमार ने राज्य के मतदाताओं से भी अपील की कि वे शांतिपूर्ण और सहभागी चुनाव प्रक्रिया को सफल बनाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है कि सभी नागरिक सक्रिय रूप से मतदान में भाग लें और शांति तथा सौहार्द बनाए रखें।

निर्वाचन आयोग के अनुसार, आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक और सुरक्षा संबंधी तैयारियां तेज कर दी गई हैं, ताकि राज्य में मतदान पूरी तरह स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सके।

عورت گھریلو نظام کی روح اور خاندانی استحکام کا مرکزی ستون ہے: پروفیسر اقتدار محمد خان

''ومن سیل'' اور ''صنفی آگہی کمیٹی''، شعبہ اسلامک اسٹڈیز کی جانب سے عالمی یوم خواتین کی مناسبت سے پروگرام کا انعقاد

نئی دہلی: ''اسلام میں عورتوں کے حقوق اور ان کے مقام و مرتبے کو صدیوں پہلے ہی واضح اور متعین کر دیا گیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اسلام کی حقیقی تعلیمات کو سمجھیں اور انہیں اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا عملی حصہ بنائیں۔ اگر مرد دیانت داری اور ذمے داری کے احساس کے ساتھ عورت کے جائز اور شرعی حقوق ادا کرے اور معاشرہ ان حقوق کے احترام اور تحفظ کو یقینی بنائے تو خواتین سے متعلق بہت سے مسائل خود بخود ختم ہو سکتے ہیں اور ایک ایسا معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے جو عدل، توازن اور باہمی احترام کی مضبوط بنیاد پر قائم ہو۔'' ان خیالات کا اظہار پروفیسر اقتدار محمد خان، صدر شعبہ اسلامک اسٹڈیز اور ڈین، فیکلٹی آف ہیومینٹیز اینڈ لینگویجز، جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی نے شعبہ اسلامک اسٹڈیز کی ''ومن سیل'' اور ''صنفی آگہی کمیٹی'' کے زیر اہتمام عالمی یوم خواتین کی مناسبت سے منعقد ایک پروگرام کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے مزید فرمایا کہ خواتین کی بااختیاری کے جدید مباحث میں عموماً تعلیم، ملازمت اور معاشی خود مختاری جیسے پہلوؤں کو مرکزی حیثیت دی جاتی ہے۔ بلاشبہ یہ امور اپنی جگہ نہایت اہم ہیں، تاہم اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ عورت خاندان کی بنیاد اور گھریلو نظام کے توازن، استحکام اور تربیت نسل کی مرکزی قوت ہے، نیز گھر کی تنظیم و ترتیب، بچوں کی مؤثر تربیت اور خاندانی مسائل کے حل میں اس کی حکمت، صبر اور بصیرت کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ پروفیسر سید شاہد علی، سابق صدر شعبہ اسلامک اسٹڈیز نے کہا کہ اسلام کی نگاہ میں مرد اور عورت میں سے کوئی بھی بذاتِ خود دوسرے سے برتر نہیں ہے، بلکہ دونوں ایک دوسرے کا تکملہ ہیں اور ان کی حقیقی فضیلت کا معیار جنس نہیں، بلکہ تقویٰ ہے۔ ڈاکٹر محمد ارشد، مشیر، ومن سیل نے اس موقع پر کہا کہ اسلام کی نظر میں عورت محض معاشرے کا حصہ نہیں، بلکہ خاندان اور تہذیب کی بنیاد اور نسلوں کی معمار ہے۔ ڈاکٹر ندیم سحر عنبرین، انچارج، ومن سیل نے کلمات تشکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی معاشرے میں عورت کا مقام محض حقوق کے مطالبے تک محدود نہیں، بلکہ عزت، وقار اور ذمہ داری کے متوازن تصور سے عبارت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس موقع پر مضمون نویسی بہ عنوان ''رمضان کی روحانیت کی بقاء میں خواتین کا کردار'' اور مباحثہ بہ عنوان ''اسلام میں خواتین کی بااختیاری: روایتی اور جدید نقطۂ نظر'' کے مقابلے کا انعقاد کیا گیا، اس میں جامعہ کے مختلف شعبوں کے طلبہ وطالبات کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مباحثہ میں پہلا انعام محمد عثمان، دوسرا آمنہ، تیسرا ذیشان اور تشجیعی انعام عذرا شفیع شاہ نے حاصل کیا۔ حکم کے فرائض ڈاکٹر جاوید اختر، ڈاکٹر اویس منظور ڈار اور ڈاکٹر انیس الرحمن نے انجام دیے۔ پروگرام کا آغاز شعبہ کی طالبہ اقصیٰ عزیز کی تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ نظامت کے فرائض علما نے انجام دیے۔ اس موقع پر شعبہ کے جملہ اساتذہ جناب جنید حارث، ڈاکٹر محمد مشاق، ڈاکٹر محمد خالد خان، ڈاکٹر محمد عمر فاروق، ڈاکٹر خورشید آفاق، ڈاکٹر عبدالوارث خان، ڈاکٹر محمد اسامہ اور ڈاکٹر محمد علی کے علاوہ طلبہ وطالبات کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ پروگرام کو کامیاب بنانے میں شعبہ کے ریسرچ اسکالر محمد اکرم، بزم طلبہ کی جنرل سکریٹری خدیجہ، محمد اسحق، شہزادی شاہین، زویا ہارون، احسان، مہرین اور ادیبہ عالم وغیرہ کا اہم کردار رہا۔

اڈیشہ میں پانی میں ڈوبنے سے 5 طالبات کی جان گئی

اڈیشہ: بورڈ امتحانات ختم ہونے کے بعد اڈیشہ کے کوراپٹ اور میور بھنج اضلاع میں المناک حادثات سامنے آئے ہیں۔ یہاں مختلف واقعات میں 5 اسکولی طالبات کی ڈوبنے سے موت ہو گئی۔ ان افسوسناک واقعات نے ریاست کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ وہیں کانگریس اور بیجو جنتا دل (بی جے ڈی) جیسی سیاسی پارٹیوں نے گہرے رنج وغم کا اظہار کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق کوراپٹ ضلع واقع کولمب تالاب میں 10 ویں جماعت کی 3 طالبات کی ڈوبنے سے موت ہو گئی۔ یہ طالبات اپنے اسکول سے نکلی تھیں اور 10 ویں کے بورڈ امتحان ختم ہونے کے بعد اپنے والدین کے آنے کا انتظار کر رہی تھیں۔ امتحانات مکمل ہونے کی خوشی میں وہ پانی میں کھیلنے کے لیے اتر گئیں جہاں وہ ڈوب گئیں۔ مقامی لوگوں نے طالبات کو بچانے کی کوشش کی اور انہیں فوری طور پر کوراپٹ کے شہید لکشمن نائک میڈیکل کالج اور اسپتال لے جایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دے دیا۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ ہفتے کو دوپہر 3 سے ساڑھے 3 بجے کے درمیان پیش آیا۔ متوفی طالبات کی شناخت لنگراج خیل (16)، سواستیک (15) اور اوم پرکاش (16) کے طور پر کی گئی ہے۔ متوفیوں کے اہل خانہ نے اسکول انتظامیہ پر لاپرواہی کا الزام عائد کرتے ہوئے واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ میور بھنج ضلع میں ایک دیگر واقعہ میں کپت پاڑا تھانہ علاقے کے کچھی پور گاؤں کے قریب تالاب میں نہاتے وقت دوسری جماعت کی دو طالبات کی ڈوبنے سے موت ہو گئی۔ 7 سالہ سبھاش سندھیا نائک اور 8 سالہ راج لکشمی سنکھوال اسکول سے واپسی کے بعد تالاب میں نہانے گئی تھیں۔ گھر والوں کو جب واردات کا علم ہوا تو وہ فوراً تالاب کے طرف بھاگے اور دونوں لڑکیوں کو پانی سے باہر نکال کر کپت پاڑا اسپتال لے جایا گیا۔

پنجاب اسمبلی کو بم سے اڑانے کی دھمکی، کابینہ کے ساتھ موجود تھے وزیر اعلیٰ، کمانڈو نے سنبھالا مورچہ

پنجاب اسمبلی کے بجٹ اجلاس کے دوران (اتوار) کو اس وقت کھلبلی مچ گئی جب ایک دھمکی آمیز ای میل موصول ہوئی۔ ای میل میں اتوار کو پنجاب اسمبلی کو بم سے اُڑانے کی دھمکی دی گئی ہے۔ سیکورٹی ایجنسیاں اس وقت ہائی الرٹ پر ہیں اور پورے اسمبلی احاطے کی مکمل تلاشی لی گئی ہے۔ حالانکہ اس دوران کوئی مشتبہ چیز نہیں ملی ہے۔ اطلاعات کے مطابق پنجاب اسمبلی کو اتوار کی صبح بم سے اُڑانے کی دھمکی ملی تھی۔ بجٹ اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ بھگونت سنگھ مان سمیت پوری کابینہ موجود ہونے پر پولیس اور سیکورٹی ایجنسیوں نے فوری مورچہ سنبھال لیا۔ جگہ جگہ کمانڈوز تعینات کیے گئے اور پورے احاطے میں چپے چپے کی جانچ کی گئی۔ بم اور ڈاگ اسکواڈ نے جانچ مہم چلائی۔ کوئی دھماکہ خیز مواد نہ ملنے پر راحت کی سانس لی گئی۔ رکن شاہ والا کے رہنے والے انجینئر گرنکھ سنگھ کے نام سے بھیجی گئی ای میل میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ حملہ آئی ای ڈی سے بھری کار یا ڈرون کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ ای میل میں پنجاب کی سیاسی قیادت اور بین الاقوامی مسائل کا ذکر کرتے ہوئے 'خالصتان نیشنل آرمی' کا نام لیا گیا ہے۔ یہ دھمکی اس وقت آئی ہے جب پنجاب حکومت آج اپنا بجٹ پیش کرنے والی ہے۔ پولیس اور انٹیلی جنس ایجنسیاں ای میل کے آئی پی ایڈریس اور بھیجنے والے کی لوکیشن کا پتہ لگانے میں مصروف ہیں۔ بجٹ پیش کئے جانے والے دن اسمبلی احاطے اور گردونواح میں سیکورٹی کے سخت انتظامات کئے گئے ہیں۔ بم اسکواڈ، ڈاگ اسکواڈ اور سیکورٹی ایجنسیوں نے پورے احاطے کی باریک بینی سے جانچ کی۔ حکام کا کہنا ہے کہ معاملے کی سنجیدگی سے تحقیقات کی گئی مگر کوئی مشتبہ چیز نہیں ملی ہے۔ دھمکی کے بعد سیکیورٹی مزید چوکس کر دی گئی ہے۔ بتادیں کہ چندی گڑھ میں بم کی یہ پہلی دھمکی نہیں ہے۔ اس سے قبل اسکولوں سے لے کر ہائی کورٹ کی عمارت تک ہر چیز کو بم سے اڑانے کی دھمکیاں دی جاتی رہی ہیں۔

'امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ میں کیا ہوگا، اس کی پیش گوئی ناممکن ہے'، کیرلم میں راہل گاندھی کا خطاب

لوک سبھا میں حزب اختلاف کے قائد راہل گاندھی نے امریکہ اور ایران کے درمیان جاری جنگ پر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انھوں نے کہا ہے کہ ''ہمارے لاکھوں بھائی اور بہنیں مشرقِ وسطیٰ میں رہتے ہیں، جو وہاں سے ہندوستان پیسے بھیجتے ہیں۔ وہ اس بات کو لے کر فکر مند ہیں کہ جنگ کی موجودہ حالت میں کیا ہوگا۔'' یہ بیان انھوں نے کیرلم میں ایک عوامی جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے دیا۔ انھوں نے کہا کہ ''حقیقت یہ ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ جنگ میں کیا ہوگا، اس کی پیش گوئی کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ لیکن ایک بات اعتماد کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ ہم دنیا میں ایک نئے، غیر مستحکم اور خطرناک دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں محتاط رہنا ہوگا، اپنی طاقت اور اپنے لوگوں کا تحفظ کرنا ہوگا۔'' دراصل راہل گاندھی کیرلم میں 'پتھو یوگا یاترا' کی ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے، اور اس دوران انھوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ساتھ کیرلم کے وزیر اعلیٰ پینارائی وجین کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ وزیر اعظم مودی کو ایک خوفزدہ وزیر اعظم ٹھہراتے ہوئے انھوں نے کہا کہ ''نریندر مودی امریکی صدر ٹرمپ کے قبضہ میں ہیں۔ صدر ٹرمپ برسر عام ہندوستانی وزیر اعظم کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ وہ صاف کہتے ہیں کہ وہ پی ایم مودی کے سیاسی کیریئر کو تباہ کر سکتے ہیں۔'' انھوں نے آگے کہا کہ ''جس طرح مودی کو ٹرمپ کنٹرول کرتے ہیں، اسی طرح مودی کیرالہ کے وزیر اعلیٰ کو کنٹرول کرتے ہیں۔'' وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ''سی بی آئی اور ای ڈی ملک بھر میں اپوزیشن لیڈران کے خلاف تیزی سے کارروائی کرتے ہیں، لیکن کیرالہ کے وزیر اعلیٰ کو ہاتھ تک نہیں لگا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک ساتھ کام کر رہے ہیں۔'' کانگریس رکن پارلیمنٹ نے کیرلم کے لوگوں کی تعریف بھی کی اور کہا کہ مشکل وقت میں ہمیشہ انھوں نے ساتھ دیا۔ راہل گاندھی کا کہنا ہے کہ ''جب بی جے پی اور آر ایس ایس میری بے رحمی اور شدت کے ساتھ مسلسل مخالفت کر رہے تھے، اس وقت کیرالہ نے مجھے گلے لگایا۔ کہا جاتا ہے کہ مشکل وقت میں ہی یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے حقیقی دوست کون ہیں۔ سب سے مشکل وقت میں مجھے معلوم ہوا کہ کیرلم میرا دوست ہے۔ صرف دوست ہی نہیں بلکہ میرا محافظ بھی ہے۔'' وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ''کیرلم کی عوام نے مجھے بہت اپنائیت کا احساس کرایا ہے۔ اس لیے میں کیرلم کی عوام کے بہتر مستقبل کی تعمیر کے لیے وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہوں جو وہ چاہتے ہیں۔ میں ہمیشہ کیرلم کی عوام کا سپاہی رہوں گا۔'' راہل گاندھی نے تقریب میں جمع بھیڑ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ 'سی پی آئی' کا مطلب 'کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا' نہیں ہے، بلکہ 'کارپوریٹ پارٹی آف انڈیا' ہے۔ انھوں نے پینارائی وجین کی حکومت کو کیرالہ کی تاریخ میں سب سے زیادہ کارپوریٹ نواز حکومت قرار دیا۔ ساتھ ہی انھوں نے کہا کہ یہ حکومت مزدوروں، چھوٹے کاروباریوں اور کسانوں کے مفادات کے خلاف ہے، یہ بڑے کاروباری گھرانوں کے مفادات کے حق میں کام کر رہی ہے۔ کیرلم کے لوگوں سے راہل گاندھی نے وعدہ کیا کہ وہ ان کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کریں گے۔ انھوں نے کہا کہ ''ہر کوئی جانتا ہے ایل ڈی ایف حکومت نے کیرلم میں بے روزگاری کا ایک بڑا مسئلہ پیدا کر دیا ہے۔ مودی نے ہندوستان میں روزگار کے نظام کو تباہ کیا، اور سی پی آئی (ایم) نے کیرلم میں روزگار کے نظام کو برباد کر دیا۔'' انھوں نے عزم ظاہر کیا کہ کانگریس حکومت بننے کے بعد کیرالہ میں روزگار کے مواقع دوبارہ پیدا کرنے کے لیے ضروری اقدام اٹھائے جائیں گے۔

विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

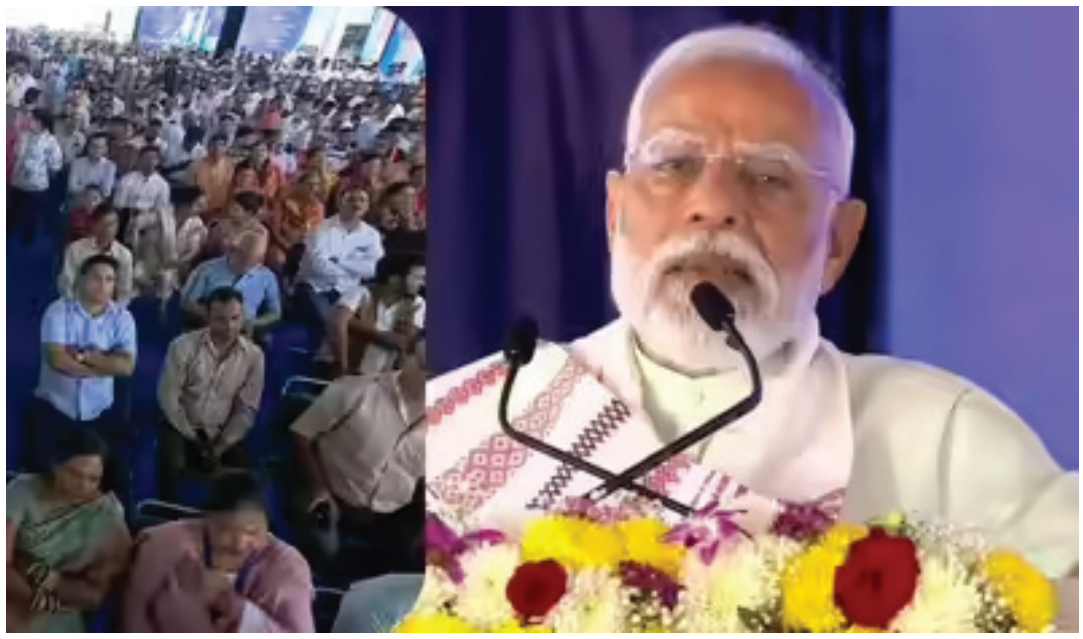

नई दिल्ली : (टॉप ब्यूरो) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में लगभग 33 हजार 500 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को लगातार मजबूत और विस्तारित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज शुरू की गई परियोजनाओं से बुनियादी ढांचा सुदृढ़ होगा, कनेक्टिविटी में सुधार होगा और लोगों का जीवन सुगम बनेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए मेट्रो खंड से राजधानी के लाखों निवासियों को महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत, महिला सशक्तिकरण में एक नया अध्याय लिख रहा है और महिलाएं देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में राष्ट्रीय राजधानी निरंतर विकास पथ पर अग्रसर है। मोदी ने कहा कि भारत की महिला शक्ति हर क्षेत्र में नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रही है और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।

प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने लगभग दस वर्षों तक विकास कार्यों को रोक रखा था। उन्होंने कहा कि अब भाजपा सरकार दिल्ली से विभिन्न चुनौतियों के समाधान के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। मोदी ने कहा कि सरकार यमुना सफाई के लिए भी बड़े पैमाने पर काम कर रही है, जिसके तहत करोड़ों रुपये की परियोजनाएं चल रही हैं।

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के कार्यक्रम में हुई चूक पर प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर राष्ट्रपति का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मुर्मु आदिवासी समुदाय के एक प्रमुख उत्सव में शामिल होने के लिए पश्चिम बंगाल गई थीं और टीएमसी ने राष्ट्रपति का सम्मान करने के बजाय कार्यक्रम का बहिष्कार किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू स्वयं आदिवासी समुदाय से आती हैं और उन्होंने हमेशा संथाल आदिवासी समाज के विकास के लिए चिंता व्यक्त की है। मोदी ने कहा कि यह न केवल राष्ट्रपति का अपमान है, बल्कि देश के संविधान और लोकतंत्र की महान परंपराओं का भी अपमान है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज शुरू हुए नये मेट्रो खंड से राजधानी के लाखों निवासियों को लाभ मिलेगा। मोदी ने 18 हजार 300 करोड़ रुपये की दिल्ली मेट्रो परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने दिल्ली मेट्रो के दो नए कॉरिडोर का भी उद्घाटन किया। इनमें मजलिस पार्क-मौजपुर बाबरपुर (पिंक लाइन) कॉरिडोर और दीपाली चौक-मजलिस पार्क (मैजेंटा लाइन) कॉरिडोर शामिल हैं। इस नई कनेक्टिविटी से दिल्ली के बुराड़ी, भजनपुरा, यमुना विहार, मधुबन चौक, भलस्वा, मजलिस पार्क इलाकों को लाभ होगा।

प्रधानमंत्री ने दिल्ली मेट्रो के चरण 5-ए के तहत 16 किलोमीटर से अधिक लंबाई के तीन नए कॉरिडोर का भी शिलान्यास किया। ये कॉरिडोर हैं - आर.के. आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ, एयरोसिटी से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल-1 और तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज। इन नए कॉरिडोर से राष्ट्रीय राजधानी के कई महत्वपूर्ण स्थानों को सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी और नोएडा, दक्षिण दिल्ली तथा हवाई अड्डे के बीच आवागमन में सुधार होगा।

आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने इस अवसर पर कहा कि मेट्रो रेल दिल्ली की जीवनरेखा बन गई है। उन्होंने कहा कि 2013-14 से पहले देश के केवल पांच शहरों में लगभग 245 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क था। श्री मनोहर लाल ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में मेट्रो और नमो भारत आरआरटीएस नेटवर्क लगभग 1100 किलोमीटर हो गया है। उन्होंने ने कहा कि भारत, मेट्रो रेल नेटवर्क की दृष्टि से अमरीका और चीन के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और आवास तथा शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू सहित अन्य लोग भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इससे पहले, प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली के सरोजिनी नगर स्थित सामान्य पूल आवासीय सुविधा - जीपीआरए टाइप फाइव का दौरा किया और महिला आवंटियों को चाबियां सौंपीं। इस अवसर पर मोदी ने श्रमजीवियों से बातचीत भी की।

प्रधानमंत्री मोदी ने जीपीआरए पुनर्विकास योजना के तहत 15 हजार 200 करोड़ रुपये की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। नई दिल्ली के सरोजिनी नगर, नेताजी नगर, कस्तूरबा नगर और श्रीनिवासपुरी जैसे प्रमुख स्थानों पर ये परियोजनाएं, जीपीआरए कॉलोनियों के आधुनिकीकरण और सरकारी कर्मचारियों तथा प्रशासनिक कार्यालयों के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार करने के सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का हिस्सा हैं। इनका पुनर्विकास सरकारी खजाने पर बोझ डाले बिना एक अभिनव आत्मनिर्भर वित्तीय मॉडल के तहत किया गया है। पुनर्विकास योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए नौ हजार 350 से अधिक आधुनिक फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे और लगभग 48 लाख वर्ग फुट कार्यालय स्थान का विकास किया जाएगा। इससे प्रशासनिक दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी

बिहार राजनीति में हलचल, नीतीश कुमार ने राज्यसभा सीट के लिए भरा पर्चा

अब यह देखना बाक़ी है JDU को बिहार से कब तक साफ़ कर दिया जाता है!

बिहार की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके नामांकन के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पटना पहुंचे।

इससे पहले अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए नीतीश कुमार ने स्वयं राज्यसभा उम्मीदवार बनने की पुष्टि कर दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट साझा कर इसकी जानकारी दी।

इस घटनाक्रम के साथ ही लगभग दो दशकों बाद बिहार की सत्ता में बड़े बदलाव की संभावना लगभग तय मानी जा रही है। पिछले कुछ समय से बिहार के राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज थी कि नीतीश कुमार राज्य की सत्ता से हटकर राज्यसभा का रुख कर सकते हैं।

इसे बिहार की सियासत में आने वाले बड़े राजनीतिक परिवर्तन का संकेत भी माना जा रहा है।सोशल मीडिया पोस्ट में नीतीश कुमार ने लिखा, 'पिछले दो दशक से भी अधिक समय

से आपने अपना विश्वास और समर्थन मेरे साथ बनाए रखा है। उसी के बल पर हमने पूरी निष्ठा के साथ बिहार और आप सभी की सेवा की है।'

उन्होंने आगे कहा, 'आपके विश्वास और समर्थन की ताकत से ही बिहार आज विकास और सम्मान का नया आयाम स्थापित कर रहा है। इसके लिए मैं पहले भी कई बार आप सभी के प्रति आभार व्यक्त कर चुका हूं।' नीतीश का कहना है, 'संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूँ. इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूँ. ''मैं आपको पूरी ईमानदारी से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके साथ मेरा यह संबंध भविष्य में भी बना रहेगा एवं आपके साथ मिलकर एक विकसित बिहार बनाने का संकल्प पूर्ववत कायम रहेगा. जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन रहेगा. '

देखना यह है की छ्ष्ठ पूरी तरह से बिहार से कब तक समाप्त होती है , क्योंकि बीजेपी का इतिहास कुछ ऐसा है जिसको उसने अपने साथ जोड़ा वो पार्टी ही ख़त्म हो जाती है बीजेपी रफ्ता रफ्ता नितीश कुमार को बिहार की राजनीती से दरकिनार करने की योजना बना रही है.

अब यह देखना बाक़ी है छ्ष्ठ को बिहार से कब तक साफ़ कर दिया जाता है. क्योंकि बीजेपी की राजनीती का एक हिस्सा यह है की वो जब किसी क्षेत्रीय पार्टी के साथ मिलती है तो उसको ख़तम कर देती है.

मिसाल के तौर पर बिहार में George Fernandes की समता पार्टी , हरियाणा में बंसी लाल की हरियाणा विकास पार्टी, महाराष्ट्र में शिव सेना, ह्रश्च में मायावती की बहुजन समाज पार्टी, आंध्र प्रदेश में तेलगु देशम पार्टी ये सब अपना वुजूद खो बैठी हैं.

لوک سبھا میں اسپیکر اوم برلا کو ہٹانے کی تحریک پیش، بحث کے لیے 10 گھنٹے مقرر

نئی دہلی: لوک سبھا میں منگل کے روز اس وقت سیاسی گرما گرمی دیکھنے کو ملی جب کانگریس کی جانب سے اسپیکر اوم برلا کو عہدے سے ہٹانے کے لیے تحریک پیش کی گئی۔ تحریک پیش ہوتے ہی ایوان میں قواعد و ضوابط کو لے کر حکمراں جماعت اور اپوزیشن کے درمیان تیز نوک جھونک شروع ہوگئی، تاہم بعد میں ایوان نے اس تحریک پر بحث کی اجازت دے دی اور اس کے لیے مجموعی طور پر دس گھنٹے مقرر کیے گئے۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ محمد جاوید نے باضابطہ طور پر یہ تحریک پیش کی۔ اس تحریک پر اپوزیشن کے 118 ارکان پارلیمنٹ کے دستخط موجود ہیں۔ اپوزیشن کا الزام ہے کہ اسپیکر اوم برلا نے ایوان کی کارروائی کے دوران غیر جانبدارانہ طرز عمل اختیار نہیں کیا اور بعض مواقع پر حکمراں جماعت کے حق میں جھکاؤ ظاہر کیا۔ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی کو بولنے کا موقع نہیں دیا گیا جس کی وجہ سے اپوزیشن میں ناراضی پیدا ہوئی۔ تحریک پیش ہونے کے بعد ایوان میں ایک نیا آئینی اور ضابطہ جاتی سوال بھی سامنے آیا۔ بحث اس بات پر ہونے لگی کہ جب اسپیکر کو ہٹانے کی تحریک زیر غور ہو تو اس دوران ایوان کی کارروائی کی صدارت کون کرے گا۔ اس وقت ایوان کی کارروائی بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ جگدمبیکا پال کی صدارت میں چل رہی تھی۔ اس معاملے پر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے رکن پارلیمنٹ اسدالدین اویسی اور ترنمول کانگریس کے رکن پارلیمنٹ سوگت رائے نے پوائنٹ آف آرڈر اٹھایا۔ اسدالدین اویسی نے پارلیمانی قواعد کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جب اسپیکر کے خلاف تحریک زیر بحث ہو تو اسپیکر یا ان کی جانب سے نامزد کیا گیا رکن ایوان کی کارروائی کی صدارت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب تک لوک سبھا میں ڈپٹی اسپیکر کی تقرری نہیں کی گئی ہے۔ ایسے میں جو رکن اس وقت چیئر پر موجود ہیں انہیں اسپیکر کی منظوری سے نامزد کیا گیا ہے، اس لیے ان کے ذریعے اس تحریک پر بحث کرانا مناسب نہیں ہوگا۔ اویسی نے یہ بھی تجویز دی کہ بحث شروع ہونے سے پہلے ایوان کو اس بات پر اتفاق کر لینا چاہیے کہ کارروائی کی صدارت کون کرے گا۔ اس کے جواب میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے بھی وضاحت پیش کی گئی۔ بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ نشی کانت دوبے نے کہا کہ پارلیمانی قواعد کے مطابق چیئر پر بیٹھا کوئی بھی رکن اسپیکر کے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے کارروائی چلا سکتا ہے۔ مرکزی وزیر برائے پارلیمانی امور کرن رجیجو نے بھی نشی کانت دوبے کے موقف کی تائید کی اور کہا کہ قواعد چیئر کو کارروائی چلانے کا واضح اختیار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق ایوان کی کارروائی کو ضابطے کے مطابق آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب کانگریس کے رکن پارلیمنٹ کے سی وینوگوپال نے حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اب تک ڈپٹی اسپیکر کی تقرری نہیں کی گئی جو ایک سنجیدہ معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بحث آگے بڑھانے سے پہلے ایوان کو یہ طے کرنا چاہیے کہ کارروائی کی صدارت کون کرے گا تاکہ کسی بھی قسم کی آئینی پیچیدگی سے بچا جا سکے۔ اس دوران بی جے پی کے سینئر رکن پارلیمنٹ روی شنکر پرساد نے بھی مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ جو رکن اس وقت چیئر پر موجود ہے اسے ایوان کی کارروائی چلانے کا مکمل اختیار حاصل ہے اور قواعد کے مطابق کارروائی جاری رکھی جا سکتی ہے۔ دونوں جانب سے دلائل سننے کے بعد ایوان کی صدارت کر رہے جگدمبیکا پال نے کہا کہ اسپیکر کا عہدہ خالی نہیں ہے، اس لیے چیئر کو کارروائی چلانے کا مکمل اختیار حاصل ہے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ اسپیکر اوم برلا نے خود فیصلہ کیا ہے کہ اس بحث کے دوران وہ ایوان کی صدارت نہیں کریں گے۔ جگدمبیکا پال نے مزید کہا کہ اسپیکر نے تحریک کے نوٹس میں موجود ابتدائی تکنیکی خامیوں کو درست کرنے میں فراخ دلی کا مظاہرہ کیا اور ضروری اصلاحات کے بارے میں خود اطلاع جاری کی۔ اس کے بعد کانگریس کے رکن پارلیمنٹ محمد جاوید نے باضابطہ طور پر اسپیکر کو ہٹانے کی تحریک ایوان میں پیش کی۔ آخر کار ایوان میں اتفاق کے ساتھ یہ طے کیا گیا کہ اسپیکر اوم برلا کو عہدے سے ہٹانے کی تحریک پر لوک سبھا میں مجموعی طور پر دس گھنٹے تک بحث ہوگی، جس کے دوران مختلف جماعتوں کے ارکان اپنی رائے پیش کریں گے۔

مغربی ایشیا میں جنگ سے ہندوستان کی معیشت متاثر ہو رہی ہے اور وزیر اعظم مباحثہ سے راہِ فرار اختیار کر رہے ہیں: راہل گاندھی

نئی دہلی: لوک سبھا میں حزب اختلاف کے قائد راہل گاندھی نے پیر کے روز ایک بار پھر وزیر اعظم نریندر مودی پر 'بلیک میل ہونے' کا سنگین الزام عائد کیا۔ انھوں نے میڈیا اہلکاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ''پی ایم مودی بلیک میل ہو چکے ہیں، وہ پوری طرح سمجھوتہ کر چکے ہیں اور اسی وجہ سے پارلیمنٹ میں اس مسئلہ پر بحث سے راہِ فرار اختیار کر رہے ہیں۔'' انھوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ ''اب وہ (پی ایم مودی) پارلیمنٹ کے اندر نہیں آ پائیں گے۔'' راہل گاندھی کا کہنا ہے کہ مغربی ایشیا میں جاری جنگ سے ہندوستانی معیشت متاثر ہو رہی ہے، اسے شدید نقصان ہونے والا ہے، لیکن 'کمپرومائزڈ' وزیر اعظم میں اس پر بحث کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ مہنگائی اور معاشی پہلوؤں کا ذکر کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ مغربی ایشیا کی صورت حال عوام سے جڑا ہوا مسئلہ ہے اور اس پر پارلیمنٹ میں بحث ہونی چاہیے۔ اپوزیشن اس موضوع پر بحث کا مطالبہ اس لیے کر رہی ہے کیونکہ اس کا براہ راست اثر ملک کی عوام اور ہندوستانی معیشت پر پڑ رہا ہے۔

دہلی فسادات کے ملزم شرجیل امام کو عدالت سے ملی راحت، 10 دنوں کے لیے عبوری ضمانت منظور

نئی دہلی: دہلی فسادات کے ملزم شرجیل امام کو کڑکڑ ڈوما کورٹ نے پیر کے روز ایک بڑی راحت دینے کا فیصلہ کیا۔ عدالت نے شرجیل امام کو اپنے بھائی کی شادی میں شامل ہونے اور بیمار ماں کی دیکھ بھال کے لیے 10 دنوں کی عبوری ضمانت دی ہے۔ کئی سالوں سے قید و بند کی صعوبت برداشت کر رہے شرجیل امام کے لیے یہ فیصلہ بہت اہم ہے، کیونکہ وہ کچھ وقت اپنے اہل خانہ کے ساتھ گزار پائیں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایڈیشنل سیشن جج سمیر باجپئی کی عدالت نے شرجیل امام کو 20 مارچ سے 30 مارچ تک عبوری ضمانت دی ہے۔ شرجیل امام نے عدالت میں عرضی داخل کر 10 دنوں کی عبوری رہائی کا مطالبہ کیا تھا۔ ان کی طرف سے وکیلوں نے دلیل دی کہ ان کے اپنے بھائی کی جلد ہی شادی ہونے والی ہے، ایسے میں گھر والوں کے درمیان ان کی موجودگی ضروری ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ ان کی ماں کی طبیعت ناساز ہے، جن کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی دوسرا نہیں۔ ان حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور گھریلو ذمہ داریوں کو دھیان میں رکھ کر عدالت نے غور و خوض کے بعد شرجیل امام کو عبوری ضمانت دینے کا فیصلہ کیا۔ عدالت نے اخلاقی بنیاد پر راحت دیتے ہوئے شرجیل امام کو 10 دنوں کے لیے جیل سے باہر آنے کی اجازت دی، یعنی تقریباً 10 دنوں بعد شرجیل جیل سے باہر قدم رکھیں گے۔ قابل ذکر ہے کہ دہلی کے شمال مشرقی علاقوں میں تشدد اُس وقت پیش آیا تھا، جب 2020 میں شہری ترمیم قانون اور این آر سی کو لے کر احتجاجی مظاہرے چل رہے تھے۔ تشدد اور آگ زنی کے دوران 53 لوگوں کی موت ہو گئی تھی۔ مشتعل لوگوں نے مرکزی حکومت کے فیصلوں، قومی شہری رجسٹر (این آر سی) اور شہری ترمیم قانون (سی اے اے) کے خلاف مظاہرے کیے تھے۔ دہلی پولیس کے الزامات میں مظاہرین پر کئی سنگین الزامات عائد کیے گئے ہیں۔

ایل پی جی سلنڈر کی قلت پر اپوزیشن کا مرکز پر حملہ، حکومت پر عوام کو گمراہ کرنے کا الزام

نئی دہلی: ملک کے کئی بڑے شہروں میں ایل پی جی سلنڈر کی قلت کی خبروں کے بعد اپوزیشن جماعتوں نے مرکزی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ سماجوادی پارٹی اور کانگریس کے رہنماؤں نے حکومت کی توانائی پالیسیوں اور اس کے دعووں پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت عوام کو اصل صورتحال سے آگاہ کرنے کے بجائے گمراہ کر رہی ہے۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ پرمود تیواری نے ممبئی اور بنگلورو کے بعض ریستورانوں میں ایل پی جی سلنڈر کی کمی کی خبروں پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ بھی ایل پی جی سلنڈر کی قلت کے لیے مرکزی حکومت اور پیٹرولیم کی وزارت کو ذمہ دار قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے پہلے گھریلو اور کمرشیل ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافہ کیا اور اب کئی علاقوں میں گیس سلنڈر کی فراہمی میں تاخیر کی شکایات سامنے آ رہی ہیں۔ پرمود تیواری کے مطابق بعض مقامات پر گھریلو گیس سلنڈر کی بکنگ 25 دن سے پہلے ممکن نہیں ہو رہی، جو حکومت کی پالیسی ناکامی کی علامت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہندوستان توانائی کے وسائل کے لیے بیرونی ممالک پر انحصار کر رہا ہے تو حکومت کو اس حوالے سے واضح حکمت عملی پیش کرنی چاہیے اور ملک میں گیس کی مسلسل اور منظم فراہمی کو یقینی بنانا چاہیے۔ دریں اثنا، سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ رام گوپال یادو نے ممبئی اور بنگلورو کے بعض ریستورانوں میں ایل پی جی سلنڈر کی کمی کی خبروں پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت پوری دنیا میں توانائی کے وسائل کے حوالے سے دباؤ بڑھ رہا ہے لیکن حکومت اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے بجائے یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ملک میں ایل پی جی اور پیٹرول و ڈیزل کا وافر ذخیرہ موجود ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہندوستان میں استعمال ہونے والے پیٹرول، ڈیزل اور کچے تیل کا تقریباً اسی فیصد حصہ بیرون ملک سے درآمد کیا جاتا ہے، اس لیے عالمی سطح پر سپلائی متاثر ہونے کا اثر ملک پر بھی پڑنا فطری ہے۔ رام گوپال یادو نے الزام لگایا کہ خام تیل کی فراہمی میں کمی کے باوجود مرکزی حکومت مسلسل یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ ملک میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ ان کے مطابق حکومت کی غلط پالیسیوں کے باعث ملک کو معاشی نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی معاملے پر سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ نیرج کشواہا موریہ نے بھی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ مرکز کی پالیسیوں کے سبب عام لوگوں پر پہلے ہی مہنگائی کا بوجھ بڑھ چکا ہے۔ گیس کی قیمتوں میں اضافے کے بعد اب گیس کی قلت کی خبریں سامنے آنا انتہائی افسوسناک ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مشرق وسطیٰ میں پیدا ہونے والی کشیدہ صورتحال اور جنگ جیسے حالات توانائی کی عالمی سپلائی کو متاثر کر سکتے ہیں، اس لیے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی مناسب دستیابی یقینی بنائے۔